भारत संघ और अन्य

बनाम

विद्या बागरिया

5 मई, 2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974:

धारा 3 (1) - निरोध आदेश - उच्च न्यायालय ने निरोध आदेश को वास्तव में तामील होने और निरुद्ध को हिरासत में लेने से पहले ही अपास्त कर दिया – शुद्धता – अभिनिर्धारित : निरोध आदेश के विलंबित निष्पादन, अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी आदि का प्रश्न वास्तव में काल्पनिक प्रकृति का है जब निरोध के आदेश को बिल्कुल भी क्रियान्वित नहीं किया गया था और पूर्व-निष्पादन चरण में चुनौती देने की मांग की गई थी - इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत एक निरोध आदेश प्रत्यर्थी के पति के संबंध में पारित किया गया था। प्रतिवादी के पति को हिरासत का आदेश तामील किये जाने से पहले, प्रतिवादी ने निरोध के आदेश को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर

की। अपीलार्थी ने निरोध आदेश वास्तव में तामील किया जाने और निरुद्ध को हिरासत में लिए जाने से पहले रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निरोध के आदेश को अपास्त कर दिया। इसलिए अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. निरोध आदेश के विलंबित निष्पादन, अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी और इस तरह के प्रश्न वास्तव में काल्पनिक प्रकृति के हैं जब निरोध के आदेश को बिलकुल भी निष्पादित नहीं कराया गया है और निरुद्ध ने तामील और कारावास से परहेज किया और जब निष्पादन पूर्व-चरण में चुनौती देने की मांग की जाती है। [954-ई]

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव बनाम श्रीमती अलका सुब्बाश गडिया, [1992] पूरक 1 एससीसी. 496, सैयद ताहिर बावमिया बनाम भारत सरकार के संयुक्त सचिव, [2000] 8 एससीसी. 630, भारत संघ बनाम पारसमल रामपुरिया, [1998] 8 एससीसी. 402, सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ, [2000] 3 एससीसी 409, हर राम पांडे बनाम बिहार राज्य, (2003) 10 जेटी 114 और भारत संघ बनाम अमृतलाल मनचंदा, [2004] 3 एससीसी 75, निर्भरता।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले की पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया है कि क्या निरोध के आदेश के निष्पादन से पूर्व भी रिट याचिकाकर्ता को कोई राहत उपलब्ध थी। नतीजतन, आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। [955-ई-एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 86/1999

अपराधिक डब्ल्यू.पी. सं. 286/1997 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.2.98।

अनूप जी. चौधरी, सी.वी. सुब्बा राव, बी.के. प्रसाद और वी.के. वर्मा, अपीलार्थी की और से।

महाबीर सिंह, राकेश दहिया, निखिल जैन और एम.ए. चिन्नासामी, प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया -

भारत संघ, संयुक्त सचिव कोफेपोसा, सीमा शुल्क आयोग-II, मद्रास और तमिलनाडु राज्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें रतन बागरिया के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (इसके बाद 'कोफेपोसा अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1) के तहत पारित दिनांक

19.12.95 के निरोध के आदेश को अपास्त कर दिया गया था। श्री रतन बगारिया को निरोध का आदेश तामील किये जाने से पहले, उनकी पत्नी श्रीमती विद्या बागरिया, यहाँ प्रत्यर्थी, ने भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की, जिसमें यहां अपीलकर्ता नंबर 2, जो रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर 2 था, द्वारा पारित हिरासत के आदेश को अपास्त करने के लिए रिट या कोई अन्य आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई । रिट याचिका में उन आधारों की वैधता को छूते हुए कई आधार उठाए गए थे जिन पर निरोध का आदेश पारित किया गया था। वर्तमान अपीलार्थियों ने एक जवाबी हलफनामा पेश किया। मुख्य रूप से निरोध के आदेश को वास्तव में तामील करने और निरुद्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले रिट आवेदन की सम्पोश्नियता के संबंध में एक आपत्ति ली गई थी। निरोध के आधार की वैधता के संबंध में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का भी खंडन किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि बताए गए आधार निरोध का निर्देश देने के लिए उचित और प्रासंगिक थे। उच्च न्यायालय ने उन आधारों की वैधता पर विस्तार से विचार किया जिनके आधार पर निरोध का आदेश स्थापित किया गया था। लेकिन जहां तक निरोध आदेश की वास्तविक तामील से पहले रिट याचिका की संधार्यता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उचित रूप से उल्लेख किए बिना इसे बहुत ही सामान्य और संक्षिप्त तरीके

से निस्तारित किया गया, विशेष रूप से इस प्रकार उनके ध्यान में लाया गया:

"इससे पहले कि मैं मामले में आगे बढ़ूं, मैं कह सकता हूं कि श्री शर्मा ने जिस केस कानून पर भरोसा किया है वह मुद्दे से परे है।"

रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि निरोध के आदेश में दर्शाए गए आधार कानूनी रूप से सम्पोश्नीय नहीं थे और निरोध का आदेश असम्पोश्नीय था।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने निरोध के आदेश की तामील होने से पहले ही रिट याचिका की संधार्यता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है और तर्क को खारिज करने से पहले निरुद्ध व्यक्ति को बहुत ही गुप्त तरीके से जेल में डाल दिया गया है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि रिट याचिका संधार्य योग्य थी और आधारों की वैधता का भी विधिवत परीक्षण किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाई जा सकती है। किसी भी स्थिति में, यह प्रस्तुत किया गया था कि निरोध का आदेश लगभग नौ साल पहले पारित किया गया था और श्री

बागरिया की कथित आशंकाओं और कथित आपत्तिजनक गतिविधियों की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

यह प्रश्न कि क्या निरुद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति निरोध के आदेश को उसके समक्ष प्रस्तुत या आत्मसमर्पण किए बिना चुनौती देने का हकदार है, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर इसका परिक्षण किया है। इस विषय पर प्रमुख निर्णयों में से एक भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव है और अन्य बनाम श्रीमती अलका सुभाष गड़िया और अन्य, मामला [1992] पूरक 1 एससीसी 496 है। उक्त निर्णय के पैरा 12 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया थाः

> "12. इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 226 और 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की एक बार हिरासत - दंडात्मक या निवारक -दिखाए जाने के बाद कोई भूमिका नहीं रह जाती है। यह उन सीमाओं को इंगित करने के लिए है, जिनका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय पालन करना होता है। ये सीमाएँ सामान्य और सर्वविदित हैं, और विवेक, औचित्य, नीति और अभ्यास के मामले में स्वयं लगाई जाती हैं और सभी कानूनों के तहत मामलों से निपटने के दौरान देखी जाती हैं। हालाँकि

संविधान इन शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन न्यायिक निर्णयों ने कानून की प्रकृति या शिकायत किए गए आदेश या निर्णय को ध्यान में रखते हुए वर्षों की अवधि में उन्हें विकसित किया है समाज के मुकाबले व्यक्ति के अधिकारों और हितों को संतुलित करने की आवश्यकता, जिन परिस्थितियों में और जिन व्यक्तियों द्वारा अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, मांगी गई राहत की प्रकृति आदि पर विचार किया जाना। इन परिसीमाओं को स्पष्ट करने के लिए, (i) अपील या पुनरीक्षण न्यायालयों के रूप में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, केवल कानून या तथ्यों की त्रुटियों को ठीक नहीं करते हैं; (ii) राहत के लिए वैकल्पिक उपाय के रूप में उक्त क्षेत्राधिकार का सहारा लेने की अनुमति नहीं है, जिसे मुकदमे या क़ानून द्वारा निर्धारित अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए यह खुला है कि वह कानून में दिए गए तरीके से निवारण प्राप्त करने के लिए किसी अन्य न्यायाधिकरण या यहां तक कि खुद को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर सकता है, तो न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके, कानून द्वारा बनाई गई मशीनरी को नजरअंदाज

करने की अनुमति नहीं देता है, (iii) यह आम तौर पर उन प्रश्नों के निर्धारण में प्रवेश नहीं करता है, जिनके लिए रिट का दावा किया गया है, जिसे लागू करने का अधिकार स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है; (iv) यह वैधानिक शक्ति से संपन्न प्राधिकरण द्वारा किए गए मुद्दों के निर्धारण में गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करता है, विशेषरूप से जब वे विशेषज्ञता की मांग करने वाले मामलों से संबंधित होते हैं, जब तक कि न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली असाधारण परिस्थितियां न हों, जैसे कि, जहां निर्धारण दुर्भावनापूर्ण है या बाहरी विचारों से प्रेरित है या किसी संवैधानिक प्रावधान के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है; (v) न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां, (क) संबंधित कानून के तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी के पास अपेक्षित प्राधिकार नहीं है या वह आदेश जो कानून के तहत पारित किया गया माना जाता है, आवश्यक नहीं है या संबंधित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है या उस व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है वह व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है; या (बी) जब प्राधिकारी ने अपनी शक्ति या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो या उसमें निहित अधिकार क्षेत्र

का प्रयोग करने में विफल रहा हो या इनकार कर दिया हो; या (सी) जहां प्राधिकारी ने अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है या अपनी शक्ति का उपयोग बेईमानी से या अनुचित उद्देश्य के लिए किया है; (vi) जहां न्यायालय अंतिम राहत नहीं दे सकता है, तो न्यायालय केवल अंतरिम राहत देने के लिए याचिका पर विचार नहीं करता है। यदि न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के लिए कोई अन्य सुविधाजनक या प्रभावी उपाय नहीं है, यह योग्यता के आधार पर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा और यदि न्यायालय यह पाता है कि याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यह अंतिम राहत देगा लेकिन केवल अंतरिम राहत प्रदान करके याचिका का निस्तारण नहीं करेगा; (vii) जहां प्राधिकारी की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, न्यायालय तब हस्तक्षेप करता है जब प्राधिकारी ने किसी अन्य निकाय के निर्देशों के तहत कार्य किया है या जब निष्कर्ष किसी गलत परीक्षण या किसी संविधि के गलत अर्थान्वयन के आधार पर पहुंचा है या यह उस सामग्री पर आधारित नहीं है जो तर्कसंगत रूप से संभावित मूल्य का है और उस विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक है जिसके संबंध में प्राधिकारी को खुद को संतुष्ट करना है। यदि फिर से उस

सामग्री पर विचार करके संतुष्टि प्राप्त की जाती है, जिसे प्राधिकारी उचित रूप से नहीं कर सका, या उन मामलों पर विचार करने से चूक जाता है, जिन पर वह विचार करना चाहता था, तो न्यायालय परिणामी आदेश में हस्तक्षेप करता है; (viii) उचित मामलों में न्यायालय तब भी हस्तक्षेप करता है जब व्यक्ति के किसी कानूनी या मौलिक अधिकार को गंभीर खतरा होता है, हालांकि वास्तव में उस पर आक्रमण नहीं होता है।"

सैयद ताहिर बावमिया बनाम भारत सरकार के संयुक्त सचिव औरअन्य, [2000] 8 एससीसी 630 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गया थाः

"अलका सुभाष के मामले (सुप्रा) में यह न्यायालय एक ऐसे मामले से भी सम्बंधित था जहां निरोध आदेश की तामील नहीं की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को संधार्य किया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायसंगत क्षेत्राधिकार, जो प्रकृति में विवेकाधीन है, का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं किया जाएगा जहां प्रस्तावित निरुद्ध सफलतापूर्वक आदेश की तामील से बच जाता है।

हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों के पास उचित मामले में निष्पादन-पूर्व चरण में निरोध के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यक शक्ति है, लेकिन हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही निरोध के आदेशों के निष्पादन से पहले के चरण में हस्तक्षेप करेंगी:

(i) कि आक्षेपित आदेश उस अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है जिसमे इसे पारित किया जाना तात्पर्यित है;

(ii) कि इसे किसी गलत व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित करने की मांग की गई है;

(iii) इसे गलत उद्देश्य के लिए पारित किया गया है;

((iv) कि यह अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया है; या

(v) कि जिस प्राधिकारी ने इसे पारित किया था, उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

जैसा कि हम देखते हैं, वर्तमान मामला न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए उपरोक्त पाँच अपवादों में

से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। यह तर्क दिया गया कि ये अपवाद पूर्ण नहीं हैं। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। अलका सुभाष का मामला (उपरोक्त) दर्शाता है कि यह केवल पाँच प्रकार के उदाहरण है जिनमे न्यायालय अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र निष्पादन से पहले के चरण में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अपीलार्थी ने यह तर्क देना चाहा कि जो आदेश पारित किया गया था वह अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर था लेकिन इस साधारण कारण से ऐसा दावा करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निरोध का आदेश और वह आधार जिस पर उक्त आदेश पारित किया गया है; रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है क्योंकि आदेश अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पास उसकी एक प्रति नहीं है, और इसलिए, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना सही नहीं है कि अस्तित्वहीन आदेश अस्पष्ट, बाहरी या अप्रासंगिक आधारों कर पारित किया गया था।"

भारत संघ और अन्य बनाम पारसमल रामपुरिया, [1998] 8 एससीसी 402 मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस बात पर काफी प्रकाश डालता है कि जब कोई व्यक्ति निरोध आदेश के विलंबित निष्पादन, अभ्यावेदन पर

विचार करने में देरी आदि जैसे उपलब्ध आधारों पर निरोध के आदेश को चुनौती देना चाहता है तो उसके लिए क्या उचित रास्ता अपनाना चाहिए। ये प्रश्न वास्तव में प्रकृति में काल्पनिक हैं जब निरोध के आदेश को बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किया गया है और निरुद्ध ने तामील और कारावास से परहेज किया है और जब निष्पादन-पूर्व चरण में चुनौती देने की मांग की जाती है। यह निम्नानुसार देखा गयाः

> "हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक लंबित अपील में एक बहुत ही असामान्य आदेश पारित किया गया प्रतीत होता है। इन अपीलों में भारत संघ द्वारा इसे चुनौती दी गई है। अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ 13.9.1996 को COFEPOSA अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निरोध का आदेश पारित किया गया था। आत्मसमर्पण करने से पहले प्रतिवादी ने 23.10.1996 को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और प्रस्तावित आदेश पर अंतरिम रोक प्राप्त की, जो कि अप्रभावी रह गई थी। पक्षों को सुनने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम राहत रद्द कर दी। इसके बाद, प्रतिवादी खंड पीठ के समक्ष अपील में गया और 10.1.1997 को फिर से अंतरिम राहत प्राप्त की जिसे

समय-समय पर बढ़ाया गया था। रिट अपील का अभी भी निस्तारण नहीं किया गया है।

जब रिट याचिका दायर की गई थी, तो प्रतिवादी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इन परिस्थितियों में, उचित आदेश जो पारित करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि प्रतिवादी को पहले निरोध आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाया जाए और फिर निरोध के आधारों का अध्ययन करने और संविधान के अनुच्छेद 22(5) द्वारा अपेक्षित उक्त आधारों के विरुद्ध अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने की बाद उसकी सभी शिकायतों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाए।"

सुनील फुलचंद शाह बनाम भारत संघ और अन्य [2000] 3 एससीसी 409 में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति फरार होने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद यह रुख अपना सकता है कि जिस अवधि के लिए निरोध का निर्देश दिया गया था, वह समाप्त हो गई है और इसलिए, निरोध का आदेश निष्फल है। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यदि वही तर्क उठाई भी गई तो वह बिना सार के खारिज किए जाने योग्य है। ऐसा तब और भी अधिक होना चाहिए जब निरुद्ध ने न्यायालय के आदेश प्राप्त करके आदेश की तामील और/या हिरासत में निरोध को रोक दिया हो। वास्तव में, सैयद ताहेर के मामले

(सुप्रा) में तथ्य स्थिति से पता चलता है कि 16 साल बीत चुके थे, फिर भी इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आदेश पुराना हो गया था।

इन पहलुओं को हाल ही में हरे राम पांडे बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 10 जेटी 114 और भारत संघ बनाम अमृतलाल मनचंदा और अन्य, [2004] 3 एससीसी 75 मामले में विस्तृत और व्यापक विचार के बाद एक बार फिर उजागर किया गया था।

ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में मामले पर विचार किया है कि क्या निरोध के आदेश को निष्पादित करने से पहले भी रिट याचिकाकर्ता को कोई राहत उपलब्ध थी। यह गूढ अवलोकन कि निर्णय "बिंदु से परे है", न केवल टालमटोल वाला प्रतीत होता है बल्कि इसमें दिमाग के विवेकपूर्ण प्रयोग का अभाव है। परिणामस्वरूप, आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह प्रतिवादी के लिए खुला है कि वह आत्मसमर्पण कर दे जैसा कि पारसमल रामपुरिया के मामले (सुप्रा) में देखा गया था और ऐसा तर्क ले सकता है जो संबंधित व्यक्ति के लिए कानून में उपलब्ध हैं। अमृत लाल मनचंदा के मामले (सुप्रा) में इन पहलुओं को एक बार फिर पर्याप्त रूप से उजागर किया गया था।

अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

वी. एस.

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।